प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 16 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 15 – 22 अप्रैल 2019 मूल्य पांच रूपए

चन्देल के कांग्रेस में आने से फिर बदले सियासी समीकरण

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तीन बार हमीरपुर से सांसद रह चुके सुरेश चन्देल कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। लम्बे अरसे से चन्देल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें

चल रही थी। बल्कि एक स्टेज पर तो उन्हे कांग्रेस द्वारा हमीरपुर से प्रत्याशी बनाये जाने की भी पूरी संभावना बन गयी थी। लेकिन तब मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर, पार्टी अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती ने उनसे बैठक करके इस स्थिति को रोक लिया था। बल्कि उसी दौरान चन्देल की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह से भी भेंट हुई और उनके भाजपा से बाहर जाने की सारी संभावनाओं पर विराम लग गया। कांग्रेस ने हमीरपुर से रामलाल ठाकुर को उम्मीदवार भी बना दिया। यह सब हो जाने के बाद चन्देल के कुछ समर्थकों ने उनको आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। इस सुझाव पर चन्देल का यह ब्यान आया कि वह शीघ्र ही फैसला लेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। वह भाजपा में रहेंगे या कांग्रेस में या निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे। चन्देल के इस ब्यान के बाद मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर फिर उनसे बिलासपुर मिलने गये। चन्देल के अतिरिक्त जयराम भाजपा से नाराज चल रहे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रिखी राम कौंडल से मिले। लेकिन इस मुलाकात का क्या परिणाम रहा इस पर बहुत कुछ बाहर नही आया।

अब जब मुख्यमन्त्री की मुलाकात के बाद सुरेश चन्देल विधिवत कांग्रेस में शामिल हो गये हैं तो स्वभाविक है कि इस शामिल होने के राजनीतिक अर्थ एकदम बदल जाते हैं और महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। चन्देल तीन बार हमीरपुर से सांसद रह चुके हैं इस नाते उनका अपना एक जनाधार पूरे क्षेत्र में आज भी है। वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे चुके हैं इस नाते पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी लाभान्वित रहे होंगे इसलिये आज चन्देल के जाने से भाजपा को एक झटका लगा है इसे झुठलाया नही जा सकता। फिर आज कांग्रेस न तो प्रदेश में सत्ता में है और न ही केन्द्र मे इसलिये यह आरोप नही लग पायेगा कि चन्देल किसी निजि स्वार्थ के लिये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज यही माना जायेगा कि वैचारिक मतभेद और व्यापक जनहित को सामने रखकर ही चन्देल ने भाजपा को अलविदा कहा है। फिर चन्देल तीन बार सांसद रह चुके हैं इस नाते उनके राष्ट्रीय स्तर पर कुछ शीर्ष लोगों से अच्छे रिश्ते आज भी होंगे और इन रिश्तो के कारण उनके पास उसी स्तर की सूचनाएं भी रही होंगी। बहुत संभव है कि इन सूचनाओं से प्रभावित होकर ही चन्देल ने यह फैसला लिया हो क्योंकि अभी पिछले दिनों ही शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पूर्व मन्त्री यशवन्त सिन्हा और अरूण शोरी जैसे नेता राफेल मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। आज 2014 के मुकाबले राजनीतिक हालात बदल चुके हैं तब कांग्रेस छोड़कर लोग भाजपा में जा रहे थे और आज भाजपा से भी लोग बाहर जाने लग पड़े हैं। वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवानी, डा. मुरली मनोहर जोशी और शान्ता कुमार जैसे नेता अपनी पीड़ा जग जाहिर कर चुके हैं। डा. मुरली मनोहर जोशी के नाम से तो एक पत्र भी सोशल मीडिया की चर्चा का विषय रह चुका है। फिर अभी कुछ विदेशी ऐजैन्सीयों CIA,KGB और MOSAD के नाम से भारत के चुनावों पर एक सर्वे बीबीसी के हवाले से आया है। इसमें दावा किया गया है कि एनडीए की अधिक से अधिक 158 और कम से कम 95 सीटें आयेंगी। यूपीए की अधिक से अधिक 327 और कम से कम 225 सीटें आने का आकलन किया गया है। स्वभाविक है कि इस तरह आंकलनों का अपनी ही तरह का एक प्रभाव रहता हैं बहुत लोग इस तरह के आकलनों से प्रभावित होते हैं बहुत संभव है कि सुरेश चन्देल के फैसले के पीछे भी इस तरह की सूचनाओं की एक मुख्य भूमिका रही हो।

यह तय है कि सुरेश चन्देल के जाने से भाजपा के सारे समीकरणों में बदलाव आयेगा और इसका असर प्रदेश की चारों सीटों पर पड़ेगा।

अब सी आई ए, के जी बी और मोसाद का सर्वे चर्चा में

BBC NEWS

"BJP will loose seats and Congress led UPA will win 2019 Lok Sabha polls says CIA, KGB & MOSAD Survey..."

"BJP led NDA-Worst possible Performance" = 95 Seats.

"BJP led NDA Best possible Performance" = 158 Seats

Visit BBC News for up-to-the-minute https://www.bbc.co.uk/news

"Congress led UPA-worst possible performance" = 225 Seats.

"Congresd led UPA-Best possible performance" = 327 Seats.

"Prime Minister Narendra Modi is loosing his popularity day by day in the country today. Main opposition party President Rahul Gandhi is emerging as most popular leader amongst people of India, especially after his pre poll announcement of a scheme which will ensure 250 million Indians would get 12000 Indian Rupees approximately equivalent to 150 British Pound per month."

https://www.bbc.co.uk/news

पूर्व उपमहाधिवक्ता पर भारी पड़ सकती है अभद्रता

शिमला/शैल। भाजपा अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ प्रयोग की गयी अभद्र भाषा का जवाब देते हुए कांग्रेस शासन में रहे उप महाधिवक्ता विनय शर्मा सत्ती से भी दो कदम आगे निकल गये है। उन्होंने सत्ती को जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि जो कोई सत्ती की जीभ काटकर लायेगा उसे वह दस लाख का ईनाम देंगे। विनय के इस ब्यान पर पूरी भाजपा में रोष फैल गया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के ज्ञापन दिये हैं। पुलिस ने इन ज्ञापनों का संज्ञान लेकर कारवाई भी की है। इस बवाल के बाद एक न्यूज चैनल ने विनय शर्मा को एक चर्चा के लिये बुलाया। इस चर्चा में भाजपा की ओर से प्रदेश मीडिया प्रभारी एडवोकेट प्रवीण शर्मा ने भाग लिया। इस चर्चा में सत्ती का प्रसंग उभरा और विनय शर्मा से पूछा गया कि क्या वह अपने वक्तव्य पर अब भी कायम है। इस पर कोई खेद व्यक्त करने की बजाये विनय शर्मा ने न केवल यह कहा कि वह अपने ब्यान पर कायम है बल्कि यह साथ जोड़ दिया कि वह अब दस लाख का ईनाम देंगे। न्यूज चैनल में यह ब्यान रिकार्ड हो गया है।

स्वभाविक है कि इस ब्यान पर हंगामा होना ही था क्योंकि यह एक कांग्रेस नेता ही नही बल्कि पूर्व महाधिवक्ता का ब्यान था। जोकि अधिवक्ता अधिनियम की संहिता से भी बंधे हुए हैं और जानकारों के मुताबिक यह अधिनियम इस तरह के ब्यान की ईजाज़त नही देता है। विनय के इस ब्यान पर प्रवीण शर्मा ने चुनाव आयोग को विधिवत शिकायत भेज दी है। इसी के साथ बार काऊंसिल को भी इसकी शिकायत कर दी गयी है। विनय के ब्यान की पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने निंदा की है जिनके कार्यकाल में वह उप महाधिवक्ता थे। लेकिन कांग्रेस के किसी और नेता या पदाधिकारी की इस पर कोई प्रतिक्रिया नही आयी है।

चुनाव आयोग ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या विनय उनके सदस्य हैं या नहीं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या स्टैण्ड लेती है। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि बार कॉऊंसिल इस पर क्या गंभीरता दिखाती है और प्रवीण शर्मा तथा भाजपा इस मामले को कितना और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस विवादित ब्यान के बाद विनय का सोशल मीडिया में एक फोटो भी चर्चा में आया है जिससे उसकी परेशानी और बढ़ सकती है।

Bhartiya Janta Party-Himachal Pradesh
State Office
Deepkamal Bhawan, Kamna Nagar, Chakkar, Shimla-171005
0177-2831892-93, (Fax) 0177-2832677
E-mail: presidentbjphp@gmail.com

To,

The SHO

Boileauganj, Police Station,

Shimla, H.P.

Praveen Kumar Sharma S/O Sh. Murari Lal Sharma, State Media Incharge, Bhartiya Janta Party, Himachal Pradesh. Deep Kamal Bhawan, Chakkar Shimla, H.P. .....Complainant

Versus

Vinay Sharma Advocate, Dharmashala, Distt. Kangra, H.P. Ex Deputy Advocate General Himachal Pradesh Government.

.....Respondent

Sub: Complaint under section 336, 350, 500, 505, 506 and 511 IPC, IT Act and other Electoral offences .

Sir,

The complainant (Undersigned) was invited by News 18 TV News Channel, Shimla for debate in its program on dated 17-04-2019 at 9:00 PM and the respondent Sh. Vinay Sharma was also present there in the same debate of the channel.

of offence is multiplied due to his knowledge of law, holding a position of law officer in the government in the previous congress government. He is deliberately issuing these statements and giving supari openly. Authorities, by not taking any action is unwittingly helping in creating an atmosphere of Mafia Raj.

Hence committed offences punishable under the various sections of IPC, Election and IT Laws.

That the relevant video is attached herewith for your kind perusal and necessary action.

It is therefore, requested that the appropriate legal action may kindly be initiated and Sh. Vinay Sharma be arrested immediately and may not be allowed in public at least till the polling day so as to maintain peace and law and order in the State.

Praveen

Date 18-04-2019

Praveen Kumar Sharma
(Complainant)

Copy to
Chief Electoral Office
Shimla Himachal Pradesh

जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र की खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा पर बुरा असर –डॉ. राजीवन

शिमला/शैल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी ने भारतीय हिमालय क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक बदलाव की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (सी2ई2) का आयोजन किया। 18 से 20 अप्रैल, 2019 के दौरान यह आयोजन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक बदलाव की घटनाओं पर विमर्श का बड़ा मंच है।

कार्यशाला का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन, हिमनद पिघलने, बार-बार अत्यधिक बदलाव की घटनाएं, वातावरण प्रदूषण, हिमालय क्षेत्र में पराली जलाने से प्रदूषण के दुष्परिणामों को समझना और समाधान के लिए रिमोट सेंसिंग के उपयोग पर विमर्श करना है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. एम राजीवन, सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार ने अपने संबाधन में कहा, ''जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम दिखने लगे हैं। विशेष कर मंडी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ये दुष्परिणाम अधिक स्पष्ट हैं।

इस अहम् विषय पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए आईआईटी मंडी की सराहना करते हुए डॉ. राजीवन ने कहा कि हिमालय जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से आर्कटिक क्षेत्र के साथ दुनिया के सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में एक है। जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र की खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है।

डॉ. राजीवन ने बताया,''हिमालय क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से मौसम में बदलाव की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे इस क्षेत्र में बर्फ का जमना बढ़ जाएगा और इस परिघटना को समझने के लिए गहन शोध करना होगा। संबंधित डाटा के अध्ययन से इसके प्रमाण मिले हैं कि हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक गर्म दिनों और रातों की संख्या बढ़ गई है जो ग्लोबल वार्मिंग का स्पष्ट संकेत है।''

पर्यावरण की अनिश्चितताओं से अत्यधिक बदलाव की कई घटनाएं हो रही हैं जैसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, भूकम्प और चट्टान/ जमीन का खिसकना। उपग्रहों की मदद से इनका मानचित्र तैयार किया जा सकता है और

निरंतर निगरानी रखी जा सकती है। यह कार्यशाला विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एकजुट होने और कुल मिलाकर पृथ्वी विज्ञान की क्षमताएं बढ़ाने के बारे में जानकारी आदान-प्रदान करने का मंच है।

कार्यशाला के मुख्य विषयों में हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक मौसम बदलाव की घटनाएं जैसे हिमालय क्रायोस्फीयर, जलवायु परिवर्तन, हिमालय क्षेत्र की अत्यधिक बदलाव की घटनाओं की बेहतर समझ के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और जीयोस्पेशियल तकनीक का प्रयोग आदि हैं।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. टिमथी ए. गोंज़ाल्विस, निदेशक, आईआईटी मंडी ने कहा, ''जलवायु परिवर्तन पर आईआईटी मंडी के 6 अलग-अलग डिसीप्लीन के 15 प्रोफेसर शोध कार्य कर रहे हैं। इस कार्यशाला में विभिन्न डिसिप्लीन के फैकल्टी की भागीदारी रही है और यह आयोजन कैम्पस में विभिन्न विषयों के परस्पर अध्ययन और सहयोगी परिवेश की मिसाल है।''

आईआईटी मंडी की प्रगति के बारे में प्रो. गोंज़ाल्विस ने कहा, ''संस्थान का शुभारंभ 2010 में केवल 97 विद्यार्थियों के साथ हुआ और 2018 में यह संख्या लगभग 1300 हो गई। वर्तमान में 104 फैकल्टी हैं और लगभग 900 विद्यार्थी संस्थान से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। आईआईटी मंडी शोध प्रोजेक्टों के लिए 85 करोड़ रु. से अधिक वित्तीय प्राप्त करने में सफल रहा है। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर काम करता है जैसे हिमालय क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी समाधान। संस्थान में विभिन्न विषयों के आपसी तालमेल से अध्ययन-अध्यापन का परिवेश है। इसके फैकल्टी विश्व स्तर पर शोध प्रतिस्पर्धा में संलग्न रहे हैं। आईआईटी मंडी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्युबेटर कैटलिस्ट ने 34 से अधिक स्टार्ट-अप्स को इनक्युबेट किया है।''

इस कार्यशाला का लक्ष्य भारतीय हिमालय क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक बदलाव की घटनाओं के असर को कम करने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक योजनाओं और कार्य प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए रिमोट सेंसिंग के व्यावहारिक उपयोग के बारे में गहरी सूझ-बूझ का विकास करना है।

कार्यशाला की अहमियत बताते हुए प्रो. रमेश पी सिंह, कार्यशाला के कॉर्डिनटेर और विजिटिंग फैकल्टी, आईआईटी मंडी ने कहा, ''जलवायु परिवर्तन और भावी पीढ़ियों पर इसके दुष्परिणामों को समझना जरूरी है। इस कार्यशाला में पूरे भारत के साथ-साथ यूरोप और अमेरिका के प्रतिभागी आए। पूरे भारत के 90 से अधिक वक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके लिए 200 से अधिक एब्सट्रैक्ट प्राप्त हुए और 150 को सूची में शामिल किया गया और 90 से अधिक मौखिक और पोस्टर प्रस्तुति इस कार्यशाला के दौरान होंगे।''

कार्यशाला के सह-संयोजक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, आईआईटी मंडी के एसिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. डेरिक्स पी. शुक्ला और डॉ. कला वेंकट उदय हैं।

कार्यशाला का वित्तीय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, भारत (डीएसटी, भारत सरकार, चैपमन युनिवर्सीटी, कैलीफोर्निया(इंटरनेशनल युनियन ऑफ जीयोडेसी और जीयोफिजिक्स, अंतरिक्ष शोधा समिति, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), रक्षा शोध एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने किया।

प्रसिद्ध जीयोफिजिसिस्ट प्रो. रोजर बिल्हम, युनिवर्सीटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, अमेरिका ने 'हिमालय में संभावित बड़े भूकम्प' पर एक वीडियो लेक्चर दिया। प्रो. रोजर बिल्हम जाने-माने अमेरिकी जीयोफिजिसिस्ट हैं और उनके वर्षों का शोध हिमालय क्षेत्र में भूकम्प के बारे में वर्तमान ज्ञान का आधार है।

डॉ. जी बी पंत, पूर्व निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी, पुणे ने भी कार्यशाला में इस विषय पर अपने विचार रखे। क्रिस मकएंटी, सीईओ और एगजीक्युटिव डायरेक्टर, अमेरिकन जीयोफिजिक्स युनियन ने इस अवसर पर वीडिया संदेश दिया। यह सी2ई2 कार्यशाला आईआईटी मंडी में 800 सीट के नव निर्मित ऑडिटोरियम का पहला आयोजन है।

केंद्रीय योजनाओं को ''किसान केंद्रित'' बनाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि :सुरेश कश्यप

शिमला/शैल। शिमला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने दुन विधानसभा क्षेत्र के

कुठाड़, चंड़ी, गोयला, साई, खरूची चक्का, बद्दी और बरोटीवाला में अपनी चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पांच वर्षो में जो काम करके दिखाया है वह कांग्रेस अपने शासन काल के 55 वर्षो में नहीं कर पायी है। मोदी जी के शासनकाल में भारत सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ है जो चीजें कभी नामुमकिन लगती थी उन सबको नरेन्द्र मोदी ने तेजी से धरातल पर उतारा है। पिछले पांच वर्षो में बैंक खाता मिला, 50 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान भारत में स्वास्थय बीमा आठ करोड़ लोगों को शौचालय, 6 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन और 3 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान मिले हैं।

उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि केंद्रीय योजनाओं को पहली बार ''किसान केंद्रित'' बनाना है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना इस दिशा में बड़ा कदम है और यह पहली बार है कि देश के प्रत्येक किसान को चाहे वो गरीब हो या अमीर अब उसे 6000 रूपए मिलेंगे। उन्हाने कहा कि कांग्रेस के विपरीत भाजपा ने देश हित को सर्वोपरि माना और सबसे अधिक सम्मान उस वर्ग को दिया जो देश की सीमाओं की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों का भी बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए ओ.आर.ओ.पी और राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना को दर्शाता है जबकि कांग्रेस ने केवल इस पर केवल राजनीति को उन्होने कहा कि ओ.आर.ओ.पी से सर्वाधिक फायदा हिमाचल के पूर्व सैनिकों को मिला है।

उन्होने कहा कि सवा साल की छोटी सी अवधि में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा ने अभूतपूर्व प्रगति की है इस अवधि में प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से 14,000 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता लाकर ''डबल इंजन'' की सरकार के वायदे को पूरा किया है और वृद्धावस्था पेंशन योजना, गृहणी सुविधा योजना जनमंच से प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाने के प्रयासों का आज देशभर में प्रंशसा हो रही है। उन्होने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में पर्यटन, वन्य जीवन पर्यटन, स्वास्थ्य और उद्योग की दृष्टि से अपार सम्भावनाएं है और सांसद चुने जाने पर वह इन सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से अनेको योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिन-रात मेहनत करेंगे। जिससे यहां के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। आजादी के पश्चात् कांग्रेस ने जानबुझ कर इस क्षेत्र को पिछड़ा रखने का षडयंत्र रचा था और यहां के लोगों को मात्र वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया।

प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ सप्ताह के तहत शिमला के जंगलो से हटाया जा रहा प्लास्टिक

शिमला/शैल। प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ सप्ताह के तहत वन विभाग हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्लास्टिक हटाया जा रहा है। शिमला

के ऐतिहासिक जाखू मन्दिर परिसर एवं जाखू पहाड़ी में शिमला स्थित वन विभाग हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों ने प्लास्टिक एकत्रित कर इस कार्य में योगदान दिया।

अजय कुमार प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन बल प्रमुख ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होने वन विभाग के उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वन विभाग पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है तथा आज के समय में प्लास्टिक के अत्याधिक प्रयोग से न केवल हमारे जंगल अपितु हर सार्वजनिक स्थल प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को गलने-सड़ने में सैंकड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी प्रदूषित होती है तथा इस प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थय पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि हमें कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए तथा जहां इसका प्रयोग आवश्यक है वहां हमें इसे प्रयोग उपरान्त उचित स्थान पर एकत्रित करना चाहिए जिससे इसे पुन: उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का पुन: उपयोग सड़कों में टायरिंग इत्यादि के लिए किया जा सकता है।

इस अवसर पर डा. सविता प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी, अर्चना शर्मा अति. प्रधान मुख्य अरण्यपाल तथा शिमला स्थित वन विभाग के अधिकरी व कर्मचारी उपस्थित थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक- जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

27-28 अप्रैल को नहीं होंगे नामांकन

हमीरपुर/शैल। लोकसभा चुनाव-2019 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 22 से 29 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे, इसमें 27 अप्रैल शनिवार को नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (वित्त मंत्रालय) के तहत दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। नामांकन प्रक्रिया के तहत 27 अप्रैल चौथे शनिवार को अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे।

यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव-2019 के तहत भारत चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा निर्वाचन के लिए नामांकन की तिथि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल, शनिवार को नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 तथा 28 अप्रैल रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं होंगे।

दुश्मन देशों को भी पता है कि मोदी घर में घुसकर मारता है:धूमल

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले हुए करते हुए कहा कि आंतकियों के ऊपर कार्यवाही करते हुए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उस कार्यवाही पर

उंगली उठाने वाले संजय निरुपम को कांग्रेस ने मुंबई से टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं था बल्कि उन वीर सैनिकों का, उनके शौर्य और पराक्रम का अपमान था जो घुटने और कोहनी के बल रेंग कर एलओसी के पार आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्रवाई करके सकुशल वापिस आए थे।

पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सैनिकों का सम्मान करते हैं। 70 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए लेकिन दिल्ली में अगर वीर सैनिकों की शहादत को सम्मान देने के लिए शहीद स्मारक का निर्माण करवाया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया। दूसरी तरफ कांग्रेस तो वह पार्टी है जिसके नेता कभी कहा करते थे कि रविवार के दिन छुट्टी होती है इसलिए रविवार के दिन फौज के सैनिकों की तनख्वाह काट लेनी चाहिए। लगातार 10 वर्षों तक हमारे वीर सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग करते रहे लेकिन नहीं मिली। मोदी सरकार बनी और बनते ही 283000 बुलेट प्रूफ जैकेट सेना को उपलब्ध करवाई हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की तारीख में दुश्मन देशों को भी पता है कि मोदी घर में घुसकर मारता है। इसलिए वहां के नेता कह रहे हैं कि अगर भारत में फिर से मोदी सरकार बनेगी तो वह खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देशद्रोहियों की, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी बात करने वालों की और अफजल गुरु को शहीद बताने वालों की हिमायत करने वाली कांग्रेस अपने घोषणापत्र में कहती है कि वह सत्ता में आकर देशद्रोह की धारा ही खत्म कर देंगे। सैनिकों की सुरक्षा के लिए बने कानून अफस्पा को भी कांग्रेस ने अपनी चुनावी मेनिफेस्टो में कहा है कि यदि वे सत्ता में आएंगे तो उसको हटा देंगे। यदि देश का सैनिक, और सेना ही सुरक्षित नहीं होंगी तो देश कब सुरक्षित रहेगा। इसलिए यदि देश को सुरक्षित रखना है अखंड रखना है तो मोदी को फिर से लाना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को अपना ध्येय वाक्य मानकर काम किया है। यही कारण है कि आम जनमानस के लिए चलाई गई अनगिनत लाभकारी योजनाओं से उन लोगों को भी बहुत लाभ पहुंचा है जिन्होंने मोदी को वोट नहीं डाला था। आज उन लोगों ने भी मन बना लिया है कि वह मोदी को वोट डालकर अपना और इस देश का भविष्य सुरक्षित मजबूत एवं उज्जवल करेंगे।

2 मई तक आवेदन वापिस ले सकेंगे उम्मीवार

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए चुनाव नामावली की घोषणा 10 मार्च, 2019 को की गई थी तथा इसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि घोषणा के अनुसार नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 22 अप्रैल, 2019 (सोमवार) को अधिसूचना जारी होने के साथ ही आरम्भ होगी तथा 29 अप्रैल, 2019 (सोमवार) तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत 27 अप्रैल, 2019 को चौथा शनिवार और 28 अप्रैल, 2019 को रविवार होने के कारण अवकाश वाले दिनों में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे।

नामांकन पत्रों की छंटनी 30 अप्रैल, 2019 (मंगलवार) को की जाएगी तथा 2 मई, 2019 (वीरवार) को नामांकन वापिस लेने की अन्तिम तिथि होगी।

संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त के कार्यालय में 22 अप्रैल, 2019 से 29 अप्रैल, 2019 तक प्रात: 11.00 बजे से दोपहर बाद 3.00 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र फार्म 2ए पर भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा, मण्डी संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त मण्डी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर, शिमला संसदीय क्षेत्र (अनुसूचित जाति) के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला के समक्ष भरे जाएंगे। मतदान 19 मई, 2019 (रविवार) को प्रात: 7.00 बजे से लेकर सायं 6:00 बजे तक होगा तथा मतगणना 23 मई, 2019 (वीरवार) प्रात: 8.00 बजे से आरम्भ होगी।

ऊर्जा संरक्षण में युवा पीढ़ी करे सहयोग:राजदान

शिमला/शैल। ब्यूरो ऑफ एनर्जी, उर्जा निदेशालय एवं सोशियो सर्विस आर्ट ग्रुप नई दिल्ली के सहयोग से 15 दिवसीय अभिनव कार्यशाला का शुभारम्भ जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह

में हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कला माध्यमों एवं गतिविधियों से उर्जा संरक्षण के महत्व बारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। इस अवसर पर सोशियो सर्विस आर्ट ग्रुप के सचिव अनिल के राजदान ने बताया कि यह संस्था विगत 18 वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में स्कूली बच्चों एवं युवाओं के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व और जागरूकता संचार कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के दौरान प्रतिभागी छात्र देश की उर्जा के वर्तमान परिदृश्य से परिचित होंगे और उन्हें ऊर्जा की मांग व आपूर्ति में अंतर का भी ज्ञान होगा। विशेषज्ञों का प्रयास रहेगा कि कार्यशाला में प्रत्येक प्रतिभागी, उर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक हो और भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे। बच्चों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला में नाट्य तत्वों, स्वत: स्फूर्त खेलकूद, दृश्य कला, संगीत और आधुनिक तकनीक पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि प्रतिभागियों की कला शक्ति को ओर तेज किया जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अधिशासी अभियंता विकास शर्मा ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उर्जा संरक्षण के प्रयासों में वह अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि प्रत्येक प्रतिभागी इस संदेश को अपने परिवार एवं समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाए ओर सभी को जागरूक करें। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य दुष्यंत सिंह ने कला के माध्यम से विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण के महत्व बारे विस्तृत जानकारी दी।

2021 तक हिमाचल को टी.बी.मुक्त करने का लक्ष्य

शिमला/शैल। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने जिला क्षय रोग (टी.बी.) निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए टी.बी. मुक्त हिमाचल के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने का आग्रह किया। क्षेत्रीय अस्पताल के सभागार में आयोजित इस बैठक में उन्होंने कहा कि टी.बी. मुक्त हिमाचल अभियान के तहत 2021 तक हिमाचल प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकारी संस्थानों एवं विभिन्न एनजीओ ने मण्डी जिला में सर्वेक्षण कर डाटा इकट्ठा किया है, जिसकी सहायता से क्षय रोग उन्नमूलन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि क्षय रोगी की पहचान करके समय पर ईलाज से बीमारी से निजात पाई जा सकती है। सभी अस्पतालों में इस रोग का ईलाज नि:शुल्क किया जाता है। उन्होंने निजी स्वास्थ्य संस्थानों, समाज सेवी संस्थाओं का भी आह्वान किया कि वे सभी प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में सक्रिय सहयोग दें।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानन्द चौहान ने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा इस दिशा में घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि उनके परिवार व आसपास यदि किसी व्यक्ति को कई दिनों से खांसी की शिकायत है तो उसकी जांच व उपचार अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि जिला में पूर्व में क्षय रोग के मरीज जिन्होंने निरन्तर उपचार के बाद इस बीमारी पर विजय पा ली है उन्हें 'क्षयवीर' का दर्जा दिया गया है तथा उनके माध्यम से समाज में जागरूकता की अलख जगाई जाएगी।

जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अरिन्दम राय ने जिला में चलाए जा रहे आरएनटीसीपी कार्यक्रम बारे विस्तृत जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों बारे प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनुराधा, डॉ. दुष्यंत, निजी स्वास्थय संस्थानों के प्रतिनिधि डॉ. मंजुल, डॉ. कर्णवीर सिंह, एनजीओ ऑपरेशन आसा के प्रतिनिधि अजेय कुमार, एसआरडीए के प्रतिनिधि मुन्सी राम, सुदर्शन ठाकुर सहित क्षयवीर भी उपस्थित थे।

वर्ष 2019-20 के लिये जिला सोलन को 3143 करोड़ रुपये की ऋण योजना का लक्ष्य

शिमला/शैल। उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने कहा कि जिला सोलन में वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकों के लिए कुल 3143 करोड़ रुपये की ऋण

योजना का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त ने जिला के अग्रणी बैंक यूको बैंक की वार्षिक ऋण योजना 2019-20 का विमोचन करने के बाद कही।

उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में 874 करोड़ रुपये, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र में 1286 करोड़ रुपये, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए 508 करोड़ रुपये जबकि गैर प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए 472 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। विनोद कुमार ने विभिन्न बैंकों से आग्रह किया कि कृषि क्षेत्र तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए बैंक अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाएं ताकि इन क्षेत्रों का समग्र विकास हो और बैंक अपने निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सफल हों।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन क्षेत्रों में पिछले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे उन्हें इस वित्तीय वर्ष में बेहतर कार्ययोजना के साथ पूरा किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि सभी बैंक वार्षिक ऋण योजना के मद्देनजर इस बात का ध्यान रखें कि कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य सभी प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण आवंटन लक्ष्य के मुताबिक रहे। उपायुक्त ने यह भी कहा कि बैंक विभिन्न ऋण मामलों की मंजूरी में अनावश्यक विलंब ना करें। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूती में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके अलावा स्वरोजगार के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक जेपी नेगी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए पीएलपी-2019 को आधार मानकर इस ऋण योजना को बनाया गया है तथा लक्ष्यों का आबंटन भी उसी को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि विभिन्न योजनाओं और स्कीमों का लाभ लोगों को मिल सके। इस समय सोलन जिला में कुल 245 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं।

वोटर स्लिप के आधार पर ही नहीं किया जा सकेगा मतदान

शिमला/शैल। मतदाता को केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक मतदाता को अपनी पहचान दर्शाने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र ना होने की सूरत में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किए गए अन्य 11 वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों और विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इसको लेकर जिले के सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

कुबेर भी यदि आय से अधिक खर्च करे तो निर्धन हो जाता है।
''चाणक्य''

सम्पादकीय

प्रज्ञा की उम्मीदवारी से उठते सवाल

लोकसभा चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें 186 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं लेकिन यह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और अब तक जो मतदान हुआ है उसमें कौन से मुद्दे प्रभावी रहे हैं इस पर वह लोग भी स्पष्ट नही है जो वोट डाल चुके हैं। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई खुलकर बहस सामने नहीं आ रही है। इसीलिये इस चुनाव के परिणाम घातक होने की संभावना बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यह चुनाव साईलैन्ट मोड़ में क्यों चल रहा है। क्या सही में देश के सामने आज कोई मुद्दा ही नही बचा है? क्या सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं। देश की समस्याओं/मुद्दों का आकलन करने के लिये यह समझना आवश्यक है कि 2014 में जब यह चुनाव हुए थे तक किन सवालों पर यह चुनाव लड़ा गया था। उस समय केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। उस सरकार के खिलाफ स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे जैसे समाज सेवीयों ने मंहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कालेधन के मुद्दे उठाये थे। इन्ही मुद्दों को लेकर लोकपाल की मांग एक बड़े आन्दोलन के रूप में सामने आयी थी। प्रशान्त भूषण जैसे बड़े वकील ने कोल ब्लॉक आवंटन टू जी स्पैक्ट्रम और कामन वैल्थ गेम्ज़ में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और शीर्ष अदालत ने भी इनका संज्ञान लेते हुए इनमें जांच के आदेश दिये थे। जांच के दौरान कई राजनेताओं, नौकरशाहों और कारपोरेट घरानो के लोगों की गिरफ्तारीयां तक हुई थी। 2014 का चुनाव इन मुद्दों की पृष्ठभूमि में हुआ और सरकार बदल गयी क्योंकि भाजपा ने उस समय इन सभी मुद्दों पर प्रमाणिक और प्रभावी तथा समयबद्ध कारवाई का वायदा करके देश में अच्छे दिन लाने का भरोसा दिलाया था।

उस समय यूपीए सरकार का मंहगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार को लेकर जो विरोध हुआ था उसे तब किसी ने भी राष्ट्रद्रोह की संज्ञा नही दी थी। तब किसी एक व्यक्ति/नेता की स्वीकार्यता के लिये वातावरण तैयार नही किया गया था। सरकार के विरोध को रोकने के लिये कोई कदम नही उठाये गये थे। परिणामस्वरूप सारा सत्ता परिवर्तन एक स्वभाविक प्रक्रिया के रूप में घट गया था। इसलिये आज जब फिर चुनाव आ गये हैं तब स्वभाविक है कि 2014 में उठे सवालों की वस्तुस्थिति आज क्या है यह जानना आवश्यक हो जाता है। उस समय पेट्रोल, डीजल की कीमतों और डालर के मुकाबले रूपये की घटती कीमतों पर नरेन्द्र मोदी से लेकर नीचे तक के एनडीए नेताओं ने जिस तर्ज पर सवाल उठाये थे आज यदि उन्ही की भाषा में वही सवाल प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरे एनडीए नेतृत्व से पूछे जायें तो शायद वह उन्हे सुन भी नही पायेंगे। भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उस समय उठे थे वह आज सारे खत्म हो गये हैं एक में भी किसी को सज़ा नही मिली है। उल्टे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में ही संशोधन करके ऐसा कर दिया है कि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत करने का साहस ही नही कर पायेगा। बेरोज़गारी के मुद्दे पर यह सामने ही है कि जो प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरीयों का वायदा किया गया था उसकी हकीकत सरकार की अपनी ही रिपोर्टो से सामने आ गयी है। सरकार की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक (जो नेशनल सैंपल सर्वे के माध्यम से सामने आयी है) नोटबंदी के बाद पचास लाख लोगों की नौकरी चली गयी है और केन्द्र सरकार तथा उसके विभिन्न अदारों में आज 22 लाख पद खाली पड़े हैं दूसरी ओर आरबीआई से आरटीआई के तहत आयी सूचना के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में 5,55,603 करोड़ के ऋण बड़े लोगों के माफ कर दिये गये हैं। यह ऋण इस देश के आम आदमी का पैसा था जिसे कुछ लोगों की भेंट चढ़ा दिया गया। स्वभाविक है कि जब इस तरह की स्थिति होगी तो कल को इसका सीधा प्रभाव मंहगाई और बेरोज़गारी पर पड़ेगा।

2014 में इन मुद्दों के कारण सरकार बदली थी लेकिन आज यह सरकार इन मुद्दों पर बात ही नही होने दे रही है। हर सवाल राष्ट्रवाद के नाम पर दबा दिया जा रहा है। जो सरकार यह दावा कर रही है कि उसके राज में कोई भ्रष्टाचार नही हुआ है वह अभी कपिल सिब्बल द्वारा नोटबंदी पर उठाये गये सवालों का जवाब नही दे पा रही है। राफेल सौदे में सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यू के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। यह आग्रह स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने पैंटागन पेपर्स पर यूएस कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले को अपने फैसले का एक आधार बनाया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि **"The concern of the government is not ot protect national security, but to protect the government officials who interfered with the negotiations in the deal"** सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद बहुत कु छ स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जब से प्रधानमंत्री पर अपरोक्ष में ''चौकीदार चोर'' का आरोप लगाया है उस पर भाजपा ने अब दो चरणों के मतदान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मामले दर्ज करवाने की बात की है। इतनी देरी के बाद भाजपा का यह कदम राजनीति की भाषा में बहुत कुछ कह जाता है। क्योंकि अब भाजपा ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को चुनाव उम्मीदवार बनाकर एक और बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव धमाकों में एक आरोपी है। महाराष्ट्र की ए. टी. एस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी मकोका के तहत हुई थी। लेकिन जब यह जांच एन आईए के पास आ गयी थी तब एक स्टेज पर एन आई ए ने मकोका को लेकर प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अदालत ने इस क्लीन चिट को स्वीकार नहीं किया और उनकी गिरफ्तारी जारी रही। अब उन्हे नौ साल जेल में रहने के बाद स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है। स्वास्थ्य कारणों पर जमानत लेने के बाद वह चुनाव लड़ रही है। उनके मामले की तब जांच कर रहे ए टी एस प्रमुख हेमन्त करकरे की मुम्बई के 26/11 के आतंकी हमले में मौत हो गयी थी। प्रज्ञा ने इस मौत को उनके श्राप का प्रतिफल कहा है। प्रज्ञा के इस ब्यान से भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया है। इस ब्यान के बाद प्रज्ञा का बाबरी मस्ज़िद का लेकर ब्यान आया। प्रज्ञा ने दावा किया है कि उन्होंने स्वयं मस्ज़िद पर चढ़कर उसे गिराने का काम किया है। चुनाव आयोग ने इस ब्यानों का संज्ञान लिया है अदालत में उनकी जमानत रद्द करने की याचिका जा चुकी है। इस परिदृश्य में प्रज्ञा को भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाना सीधे-सीधे हिन्दु ध्रुवीकरण की कवायद बन जाता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अदालत उनकी जमानत रद्द करके उन्हें जेल से ही चुनाव लड़वाती है या जमानत बहाल रखती है क्योंकि अदालत ने हार्दिक पटेल को भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी है। और हार्दिक पटेल से प्रज्ञा का मामला ज्यादा गंभीर है।

गांधी और आर एस एसः विरोधाभासी राष्ट्रवाद

राम पुनियानी

देशबन्धु से साभार:आरएसएस लगातार यह प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है कि महात्मा गांधी, संघ को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसी संदर्भ में आरएसएस के सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने एक लेख लिखा है ('द महात्मा एंड द संघ', इंडियन एक्सप्रेस, 12 अप्रैल 2019) वैद्य सबसे पहले नाथूराम गोड़से से दूरी बनाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि संघ में गांधी पर हुए जितने विमर्शों में उन्होंने भागीदारी की है, उनमें कभी गोड़से का नाम नहीं लिया गया।

क्या इसका अर्थ यह है कि गोड़से का आरएसएस से कोई लेनादेना नहीं था? गोड़से, आरएसएस का प्रचारक था, जिसने बाद में हिन्दू महासभा की सदस्यता ले ली और उसकी पुणे शाखा का सचिव बन गया। उसके छोटे भाई गोपाल गोड़से, जो गांधी हत्या प्रकरण में सह-अभियुक्त था, ने 1994 में लिखा कि उनके बड़े भाई आरएसएस की रक्षा करना चाहते थे, जो हमारे लिए ''एक परिवार की तरह है''। नाथूराम ने अपनी गवाही में कहा कि उसने आरएसएस छोड़ दिया था। गोपाल ने लिखा, ''उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस गंभीर मुश्किलों में फंस गया था। परंतु उन्होंने आरएसएस नहीं छोड़ा था।'' गोपाल ने उन लोगों की 'कायरता' की निंदा की, जिन्होंने उनके भाई की आरएसएस की सदस्यता को विवाद का विषय बनाया। गोपाल की इस गवाही का समर्थन आरएसएस-समर्थक अध्येता डॉ. कोयेनराड एल्सेट करते हैं जिन्होंने 2001 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, 'गांधी एंड गोड़से' में लिखा कि ''नाथूराम ने यह दिखाने का प्रयास किया कि आरएसएस से उनका कोई संबध नहीं है। इसका उदेश्य यह था कि संघ को हत्या के बाद के कठिन महीनों में और अधिक परेशानियां न भुगतनी पड़ें।''

अपने लेख के प्रारंभ में वैद्य बिना किसी लागलपेट के कहते हैं कि वे गांधी के विरोधी हैं परंतु उनका यह भी कहना है कि संघ के गांधी से मतभेदों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अतिवादी और जिहादी तत्वों के समक्ष समर्पण कर दिया था, आरएसएस, गांधी का प्रशंसक था। इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने का यह प्रयास, वैद्य और आरएसएस की हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप है। निश्चित रूप से देश के मुसलमानों में से कुछ मुस्लिम राष्ट्रवादी थे। गांधी उन्हें कतई पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्यधारा में शामिल किया। यह कहना कि जिन मुसलमानों ने गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था वे अतिवादी या जिहादी थे न केवल सत्य को झुठलाना है वरन् यह आरएसएस की विश्व दृष्टि को भी उजागर करता है। संघ मुसलमानों को विदेशी, आक्रांता और आतंकी मानता है। संघ की इसी विचारधारा के चलते, गोड़से ने तीन गोलियां गांधीजी के सीने में उतार दी थी।

वैद्य यह दर्शाने का प्रयास भी करते हैं कि संघ ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। वे बताते हैं कि डॉ. के. बी. हेडगेवार ने सन् 1921 के असहयोग आंदोलन और सन् 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। हेडगेवार ने असहयोग आंदोलन में भले ही भाग लिया हो परंतु उन्होंने उसके परिणामों की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण देश में उत्साह का जो वातावरण बना था, उसके ठंडा हो जाने के बाद, उन सामाजिक बुराईयों ने सिर उठाना शुरू कर दिया, जो इस आंदोलन से जन्मी थी। उनके अनुसार, इसी आंदोलन के कारण देश में ब्राहम्णों और गैर-ब्राहम्णों के बीच खुलकर टकराव होने लगा। संघ के संस्थापक हेडगेवार ने इस आंदोलन में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भाग लिया था और एक संगठन बतौर संघ ने कभी किसी ब्रिटिश-विरोधी आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं की। सन् 1930 (संघ की स्थापना सन् 1925 में हुई थी) में हेडगेवार ने उन लोगों को हतोत्साहित किया, जो ब्रिटिश-विरोधी आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। सन् 1942 में उनके उत्तराधिकारी ने संघ के स्वयंसेवकों पर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया। गोलवलकर ने संघ के स्वयंसेवकों को याद दिलाया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हमारे एजेंडा में नहीं है। ''हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस प्रतिज्ञा की चर्चा हमने की है, उसमें हमने धर्म और संस्कृति की रक्षा के जरिए देश को स्वतंत्र करने की बात कही है। इसमें अंग्रेजों के भारत से बाहर जाने का कोई जिक्र नही है।

जहां तक आरएसएस के बारे में गांधी की राय का प्रश्न है, वह कई स्थानों पर बिखरी हुई है परंतु उनके सभी कथनों और वक्तव्यों को समग्र रूप से देखने पर यह पता चलता है कि वे संघ के बारे में क्या सोचते थे। आरएसएस के बारे में गांधी की सोच का विवरण हमें कई प्रामाणिक और विश्वसनीय स्त्रोतों से मिलता है। 'हरिजन' के 9 अगस्त 1942 के अंक में गांधी लिखते हैं, ''मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी गतिविधियों के बारे में सुना है और मुझे यह भी पता है कि वह एक साम्प्रदायिक संगठन है''। गांधीजी ने यह टिप्पणी उन्हें भेजी गई एक शिकायत के बाद की थी, जिसमें एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ नारे लगाए जाने और भाषण दिए जाने की बात कही गई थी। गांधीजी को बताया गया था कि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कसरत के बाद ये नारे लगाए कि यह राष्ट्र केवल हिन्दुओं का है और अंग्रेजों के जाने के बाद हम गैर-हिन्दुओं को अपना गुलाम बना लेंगे। साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों और गुंडागर्दी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, ''मैंने आरएसएस के बारे में कई बातें सुनी हैं। मैंने सुना है कि इन गड़बड़ियों की जड़ में आरएसएस है।''

गांधी का आरएसएस का क्या आकलन था इसका सबसे प्रामाणिक सुबूत है उनके सचिव प्यारेलाल द्वारा दिया गया विवरण। प्यारेलाल लिखते हैं कि सन् 1946 के दंगों के बाद गांधीजी के काफिले के एक सदस्य ने पंजाब के शरणार्थियों के लिए वाघा में बनाए गए ट्रांसिट कैंप में आरएसएस कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता, अनुशासन, साहस और कड़ी मेहनत करने की क्षमता की तारीफ की। इस पर गांधी ने कहा ''यह न भूलो कि हिटलर के नाजी और मुसोलिनी के फासीवादी भी ऐसे ही थे''। गांधी मानते थे कि आरएसएस का दृष्टिकोण एकाधिकारवादी है और वह एक साम्प्रदायिक संस्था है।

स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में गांधी ने आरएसएस के मुखिया गोलवलकर से चर्चा की। उन्होंने गोलवलकर से कहा कि इस हिंसा के पीछे आरएसएस है। इस पर गोलवलकर ने इस आरोप से इंकार करते हुए कहा कि संघ, मुसलमानों की हत्या के पक्ष में नहीं है। गांधी ने गोलवलकर से कहा कि उन्हें सार्वजनिक रूप से ऐसा कहना चाहिए। गोलवलकर ने जवाब दिया कि गांधी उनके हवाले से यह कह सकते हैं। उस दिन शाम को आयोजित प्रार्थना सभा में गांधीजी ने गोलवलकर के इस कथन का हवाला तो दिया परंतु साथ ही यह भी कहा कि बेहतर होता कि गोलवलकर स्वयं यह बात कहते। बाद में उन्होंने नेहरू ने कहा कि गोलवलकर उन्हें बहुत विश्ववसनीय व्यक्ति नहीं लगे।

आज गांधी और गोड़से में से एक को चुनने का अर्थ है गांधी के समावेशी भारतीय राष्ट्रवाद और संघ के हिन्दू राष्ट्रवाद में से एक को चुनना। गोड़से, हिन्दू राष्ट्रवाद के पर्यायवाची हैं, जो संघ परिवार का एजेंडा है और जिसे आरएसएस की संतान भाजपा बढ़ावा दे रही है।

स्वयंसेवक जब कहे मोदी आखरी लडाई लड रहे हैं तो...

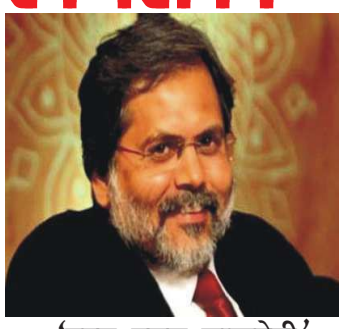

'पुण्य प्रसून बाजपेयी'

ये कलयुग है और कलयुग में ना तो महाभारत संभव है ना ही गीता का पाठ, या फिर न्याय के लिये संघर्ष। जोड़तोड़ की भी कलयुग में उम्र होती है। कलयुग में तो ताकत ही सबकुछ है और ताकत का मतलब ज्ञान नहीं बल्कि धोखा –फरेब के आसरे उस सत्ता का जुगाड है जिस जुगाड का नियम है खुद के साथ सबकुछ स्वाहा करने की ताकत। और जबतक ताकत है तबतक स्वाहा होते हालात पर कोई अंगुली नहीं उठाता। सवाल नहीं करता।

स्वयंसेवक साहेब का यह अंदाज पहले कभी नहीं था। लेकिन आप ये कह क्यों कह रह है और हम सभी तो चाय के लिये आपके साथ इसलिये जुटे है कि कुछ चर्चा चुनाव की हो जाये लेकिन आज आप सतयुग और कलयुग का जिक्र क्यों कर बैठे हैं, मुझे टोकना पडा। क्योंकि मेरे साथी आज प्रोफेसर संघ के भीतर की उस हकीकत को समझने आये थे जहां प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से उतारने के पीछे संघ है या बीजेपी। या फिर संघ अब अपने पाप–पुण्य का परिक्षण भी मोदी के 2019 के समर में कर लेना चाहता है।

दरअसल प्रोफेसर साहेब के इसी अंदाज के बाद स्वयंसेवक महोदय जिस तरह कलयुग के हालात तले 2019 के चुनाव को देखने लगे उसमें स्वयसेवक ने खुले तौर पर पहली बार माना कि मोदी–शाह की खौफ भरी बाजीगरी तले बीजेपी के भीतर की खामोश उथलपुथल। संघ का हिन्दु आंतक को लेकर प्रज्ञा के जरीये चुनाव परिक्षण और जनादेश के बाद जीत का तानाबाना लेकिन हार के हालात में बीजेपी को जिन्दा रखने का कोई प्लान ना होना संघ को भी डराने लगा है।

तो क्या संघ मान रहा है मोदी चुनाव हार रहे हैं। प्रोफेसर साहेब ने जिस तरह सीधा सवाल किया उसका जवाब पहली बार स्वयंसेवक महोदय के काफी हद तक सीधा भी दिया और उलझन भी पैदा कर दी। ....मैने आपको कहा ना ये महाभारत काल नहीं है लेकिन महाभारत का कैनवास इतना बड़ा है कि उसमें कलयुग की हर चाल समा सकती है। सिर्फ आपको अपनी मनस्थिति से हालात को जोडना है और अब जो मै कहने जा रहा हूं उसे आप सिर्फ सुनेगे....टोकेगें नहीं।

जी...मै और प्रोफेसर साहेब एक साथ ही बोल पडे। तो समझे ...संघ तो भीष्म की तरह बिधा हुआ युद्द स्थल पर गिरा हुआ है। संघ जब चाहेगा उसकी मौत तभी होगी। लेकिन मौजूदा हालात में संघ की जो ताकत बीजेपी को मिला करती थी वह मोदी के दौर में उलट चुकी है। कल तक संघ अपने सामाजिक– सांस्कृतिक सरोकारों के जरीये राजनीति का परिक्षण करता था। अब संघ को परिक्षण के लिये भी बीजेपी की जरुरत है। और इसकी महीनता को समझे तो काग्रेस की सत्ता के वक्त हिन्दु आंतकवाद का सवाल संघ को नहीं बीजेपी को डरा रहा था क्योंकि बीजेपी को संघ की ताकत और समाज को प्रभावित करने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी थी। और राजनीतिक तौर पर संघ की सक्रियता के बगैर बीजेपी की जीत मुश्किल होती रही है ये भी हर कोई जानता है। ऐसे में मोदी सत्ता काल में हिन्दु आंतकवाद की वापसी का भय सत्ता जाने के भय के साथ जोड दिया गया।

किसने जोडा....प्रोफेसर बोले नहीं कि ...स्वयंसेवक महोदय बोल पडे। प्रोफेसर साहेब पुरी बात तो सुन लिजिये. .क्योंकि आपका सवाल बचकाना है। अरे सत्ता जिसके पास रहेगी वह कतई नही चाहेगा कि सत्ता उसके हाथ से खिसक जाये। तो सत्ता बरकरार रखने के लिये उसके अपने ही चाहे नीतियों का विरोध करते रहे हो लेकिन सभी को जोडने के लिये कोई बडा डर तो दिखाना ही पडेगा। तो हिन्दु आंतकवाद का भय दिखाकर संघ को सक्रिय करने की बिसात भी मौजूदा सत्ता की ही होगी। और उसी का परिणाम है कि प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से बीजेपी के टिकट पर उतारा गया है।

लेकिन आप तो डर और खौफ को बडे व्यापक तौर पर मौजूदा वक्त में सियासी हथियार बता रहे थे।

वाजपेयी जी आप ठीक कह रहे हैं लेकिन उसकी व्यापकता का मतलब पारंपरिक तौर तरीकों को खारिज कर नये तरीके से डर की परिभाषा को भी गढना है और ये भी मान लेना है कि ये आखरी लडाई है।

आखरी लडाई.... जी प्रोफेसर साहेब आखरी लडाई । तो क्या चुनाव हारने के बाद मोदी–शाह की जोडी को संघ भी दकरिनार कर देगा।

अब ये तो पता नहीं लेकिन जिस तरह चुनावी राजनीति हो रही है उसमें आप ही बताइये प्रोफेसर साहेब क्या क्या मंत्र अपनाये जा रहे हैं।

आप अगर मोदी का जिक्र कर रहे हैं तो तीन चार हथियार तो खुले तौर पर है। जैसे– जैसे मनी फंडिंग, मनी फंडिंग का मतलब। मतलब यही कि ये सच हर कोई जानता है कि 2013 के बाद से कारपोरेट फंडिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आलम ये रहा है कि सिर्फ 2013 से 16 के बीच 900 करोड की कारपोरेट फंडिंग हुई जिसमें बीजेपी को 705 करोड मिले। इसी तरह 2017–18 में अलग अलग तरीके से पालीटिकल फंडिंग में 92 फिसदी तक बीजेपी को मिले। यहां तक की 221 करोड के चुनावी बाड में से 211 करोड तो बीजेपी के पास गये। लेकिन जब बैंक में जमा पार्टी फंड दिखाने की स्थिति आई तो 6 अक्टूबर 2018 तक बीजेपी ने सिर्फ 66 करोड रुपये दिखाये स्वयंसेवक जब कहे मोदी आखरी लडाई लड़ रहे है तो.....। और जिन पार्टियों की फंडिग सबसे कम हुई वह बीजेपी से उपर दिखे। मसलन बीएसपी ने 665 करोड दिखाये और वह टाप पर रही। तो सपा ने 482 करोड और कांग्रेस ने 136 करोड दिखाये।

तो इससे क्या हुआ–अरे स्वयंसेवक महोदय क्या आप इसे नहीं समझ रहे हैकि जिस बीजेपी के पास अरबो रुपया कारपोरेट फंडिग का आया है अगर उसके बैंक खाते में सिर्फ 66 करोड है जो कि 2013 में जमा 82 करोड से भी कम है तो इसके दो ही मतलब है । पहला , चुनाव में खूब धन बीजेपी ने लुटाया है। दूसरा, फंडिग को किसी दूसरे खाते में बीजेपी के ही निर्णय लेने वाले नेता ने डाल कर रखवा है । यानी कालेधन पर काबू करेगें या फिर चुनाव में धनबल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये । इसे खुले तौर खत्म करने की बात कहते कहते बीजेपी संभालने वाले इतने आगे बढ गये कि वह अब खुले तौर पर बीजेपी के सदस्यों को भी डराने लगे है।

कैसे डराने लगे है। डराने का मतलब है कि बीजेपी के भीतर सत्ता संभाले दो तीन ताकतवर लोगो ने बीजेपी के पूर्व के कद्दावर नेताओं तक को एहसास करा दिया है कि उनके बगैर कोई चूं नहीं कर सकता। या फिर जो चूं करेगा वह खत्म कर दिया जायेगा। इस कतार में आडवाणी, जोशी या यशंवत सिन्हा सरीखो को शामिल करना जरुरी नहीं है बल्कि समझना ये जरुरी है कि मोदी सत्ता के भीतक ताकतवर वही हुये जिसकी राजनीतिक जमीन सबसे कमजोर थी। सीधे कहे तो हारे, पीटे और खारिज कर दिये लोगों को मोदी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। और धीरे धीरे इसकी व्यापकता यही रही कि समाज के भीतर लुपंन तबके को सत्ता का साथ मिलाया तो वह हिन्दुत्व का नारा लगाते हुये सबसे ताकतवर नजर आने लगा।

तो दो हालात आप बता रहे हैं। वाजपेयी जी अपको क्या लगता है मोदी सत्ता ने जीत के लिये कौन सा मंत्र अपनाया।

स्वयंसेवक महोदय जिस अंदाज में पूछ रहे थे मुझे लगा वह भी कुछ बोलने से पहले हमारी समझ की थाह लेना चाहते हैं। बिना लाग लपेट मैने भी कहा। डर और खौफ का असल मिजाज तो छापो का है। चुनाव का एलान होने के बाद नौ राज्यो में विपक्ष की राजनीति करते नेताओं के सहयोगी या नेताओं के ही दरवाजे पर जिस तरह इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे। उसने साफ कर दिया कि मोदी अब आल वर्सेस आल की स्थिति में ले आये है। इसलिये परंपरा टूट चूकी है क्योकि मोदी को एहसास हो चला है कि जीत के लिये सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर सरीखे इक्के से काम नहीं चलेगा बल्कि हर हथियार को आजमाना होगा और इसी का असर है कि मधयप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, कश्मीर, बंगाल, ओडिसा में विपक्ष के ताकतवर नेताओ के घर पर छापे पडे।

तो क्या हुआ .... हुआ कुछ नहीं बंधुवर ..अब मुझे स्वयंसेवक महोदय को ही टोकना पडा। दरअसल हालात ऐसे बना दिये गये हैं कि सत्ता से भागीदारी करते तमाम संस्थानो के प्रमुख को भी लगने लगा कि मोदी हार गये तो उनके खिलाफ भी नई सत्ता कार्रवाई कर सकती है .... तो आखरी लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं समेत मोदी सत्ता से डरे सहमे नौकरशाहों की भी है।

तो क्या ये असरकारक होगी। कहना मुश्किल है। लेकिन मोदी का खेल इसके आगे का है इसलिये लास्ट असाल्ट के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है और संघ इससे हैरान–परेशान भी है।

मतदाता को जागरूक करने में लगे राजनैतिक दल

–डॉ. नीलम महेंद्र–

देश में एक बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं और लगभग हर राजनैतिक दल मतदाताओं को ''जागरूक'' करने में लगा है। लेकिन इस चुनाव में खास बात यह है कि इस बार ना तो कोई लहर है और ना ही कोई ठोस मुद्दे यानी ना सत्ताविरोधी लहर ना विपक्ष के पक्ष में हवा। बल्कि अगर यह कहा जाए कि समूचे विपक्ष की हवा ही निकली हुई है तो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा अब तक के लगभग हर चुनाव में विपक्षी दलों का एक महत्वपूर्ण हथियार होता था इस बार उसकी धार भी फीकी है। इस बात का एहसास देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हो गया है शायद इसलिए कल तक जिस रॉफेल विमान की सवारी करके वो सत्ता तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे थे आज वो उनके चुनावी भाषणों से ही फुर्र हो चुका है । हाँ लेकिन चौकीदार पर नारे वो अपनी हर चुनावी रैली में लगवा ही लेते हैं। लेकिन उनके चौकीदार चोर है के नारे की हवा ''मैं भी चौकीदार'' कैंपेन ने उतनी नही निकाली जितनी मात्र चार माह पुरानी खुद उनकी ही मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के करीबियों पर पड़े हाल के ई डी के छापों ने निकाल दी। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब उनके चुनावी मुद्दे खुद उन्हीं की पार्टी ने उनसे छीन लिए हों। इससे पहले भी जब तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में उनका किसानों की कर्जमाफी का कार्ड उनके लिए संजीवनी साबित हुआ था, तब उन्हें इसी कर्जमाफी में लोकसभा चुनावों की जीत की कुंजी भी दिखाई देने लगी थी। देश भूला नहीं है कि उस समय लगभग अपना राजनैतिक बनवास काट रही मृतप्राय कांग्रेस ने इन तीन प्रदेशों के किसानों को कर्जमाफी की बूटी दिखाकर कैसे सत्ता की चाबी हासिल की थी। और इस जीत से अति उत्साहित राहुल गांधी ने कहा था कि कर्जमाफी अब आने वाले लोकसभा चुनावों का अहम मुद्दा होने वाला है और हम नरेंद्र मोदी को तब तक सोने नहीं देंगे जब तक वो पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ नहीं कर देते। लेकिन तीन राज्यों में मात्र चार महीने पहले जो कर्जमाफी कांग्रेस का सफल प्रयोग और गेम चेंजर सिद्ध हुआ था आज वो कर्जमाफी उनके चुनावी भाषणों ही नहीं मेनिफेस्टो से भी गायब है। दरअसल इसकी हवा भी किसी और ने नहीं खुद कांग्रेस और उसकी भ्रष्टाचार की नीतियों ने ही निकाली है। सरकार बनने के दस दिनों के अंदर किसानों का कर्जमाफी के नाम पर तीनों प्रदेशों में जो सरकार बनी वो दस दिनों के अंदर कर्जमाफी से ज्यादा कर्जमाफी के नाम पर घोटालों के लिए जानी गई। इसलिए राहुल अब एक नया गेम चेंजर, ''न्याय'' लेकर आए हैं। देश के 20% गरीब परिवारों को साल के 72000 रूपए दिए जाएंगे। मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और अधिक से अधिक वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाने वाली कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी आरजेडी बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा सभी अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को लोकलुभावन वादे करके अपनी ओर आकृष्ट करने के नए नए तरीके अपनाते हैं। कितना हास्यास्पद है कि जो राजनैतिक दल लगातार सरकार में रहते हुए देश के आखिरी व्यक्ति को बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी वो चुनावों के दौरान इन्हें मुफ्त देने के वादे करती हैं। जिस बिहार में शराबबंदी है, उस बिहार की जनता से तेजस्वी यादव कहते हैं कि वे ताड़ी बनाना कानूनी कर देंगे। वहीं भाजपा हर चुनाव की तरह इस बार भी राम मंदिर बनाने और 370 हटाने का वादा कर रही है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये दल खुले आम संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए जाति और धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं। हाल ही में मायावती ने खुले मंच से मुस्लिम वोटरों से अपने वोटों को बंटने नहीं देने की अपील की। तो ''अली'' का जवाब योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली से दिया।

ऐसे हालतों में जब सत्ता हासिल करने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा मतदाताओं को उनके छोटे छोटे स्वार्थों का लालच दिखाकर उन्हें भारी संख्या में मतदान करने के लिए यह कहकर प्रोत्साहित किया जाता है कि आपका जागरूक होना आवश्यक है। मतदान आपका अधिकार भी है और फ़र्ज़ भी। अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों और ''देशहित'' में मतदान अवश्य करें, तो अब समय आ गया है कि देश का मतदाता अपने ''जागरूक'' होने का अर्थ समझे। क्या जागरूक होने का अर्थ सिर्फ अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना भर है ? क्या उसका फ़र्ज़ केवल अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति करना भर है? क्या उसकी नियति इन राजनैतिक दलों के हाथों की कठपुतली बनना भर है? आखिर कब वो जागरूक होगा और ''देश बचाओ संविधान बचाओ'' और देशहित जैसे शब्दों में पीछे छुपे भावार्थ ''स्वार्थ और स्वहित'' को पढ़ पाएगा? आखिर कब वो 72000 सालाना मिलने वाले ''न्याय'' के पीछे छुपे उस ''अन्याय'' को देख पाएगा जो उसे शारिरिक ही नही मानसिक तौर पर भी पंगु बनाने का कदम है? आखिर कब वो इस प्रकार की ''जनकल्याण'' घोषणाओं के पीछे छुपे खुलमखुल्ला रिश्वतखोरी को देख पाएगा?

सच तो यह है कि देश के मतदाता की नियति उस दिन बदलेगी जिस दिन वो सच में जागरूक होगा। जिस दिन वो जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचेगा, निजस्वार्थ से पहले देशहित की सोचेगा। वो जागरूक तब होगा जब वो मुफ्त में मिलने वाली हर उस चीज़ को ठुकरएगा जो उसे पंगु बनाए। वो जागरूक तब होगा जब वो अपनी भुजाएं हाथ फैलाने के लिए नहीं बल्कि मेहनत के लिए उठाएगा। तब वो जागरूक मतदाता किसी के हाथों की कठपुतली नही होगा। वो ना अली होगा ना बजरंगबली होगा केवल ''जागरूक मतदाता''होगा। और फिर वो अपनी उंगली से केवल अपनी ही नही देश की तक़दीर बदलने का भी माद्दा रखेगा।

मोदी सरकार ने 15 करोड़ लोगों को दिया रोजगार:भाजपा

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चुनाव प्रभारी प्रवीण शर्मा और जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह रोजगार के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार ने पिछले साढे 4 वर्षो में 15 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के लोग भाजपा नेताओं के बयानों को जुमले का नाम देखकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अपने दावों को पुख्ता बताते हुए उन्होंने जारी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 4 साल के दौरान एमएसएमई सेक्टर में रोजगार के ज्यादा मौके पैदा हुए हैं। सीआईआई द्वारा जारी किए गए सर्वे के अनुसार मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले 4 साल में एमएसएमई में प्रति वर्ष लगभग 1.49 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है। चार सालों में यही संख्या लगभग 6 करोड़ होती है।

उन्होंने क्षेत्रवार हर विभाग के आँकड़ों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने पिछले 4 वर्षो में 268 मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली इकाइयों ने 6.7 लाख नौकरियां सृजित की हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 4.5 वर्षो में अकेले परिवहन क्षेत्र में 1.43 करोड़ जॉब सृजित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में भी अपार नौकरियां दी गयी हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय के अनुसार पिछले 4 वर्षो में पर्यटन क्षेत्र ने 1.42 करोड़ नौकरियां सृजित की गयी हैं।

वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने पिछले 4 वर्षो में 12.29 लाख से अधिक नौकरियां सृजित कीं गयी हैं। आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में मील रोजगार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नासकॉम के अनुसार, पिछले 3 वर्षो में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में 6 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार अकेले 2017 में ही भारत के रिन्यूएबल सेक्टर में मेगा प्रोजेक्ट्स ने 1.64 लाख नौकरियां पैदा की गयी हैं। उन्होंने कहा कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षो में 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया है।

स्वरोजगार के क्षेत्र की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े 4 वर्षो में मुद्रा योजना के माध्यम से 12 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है। यही नहीं पिछले 4.5 वर्षो में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का लाभ उठाया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने पिछले 4 वर्षो में 4.90 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले 4 वर्षो में 787.55 करोड़ मानव दिन के रोजगार का सृजन किया गया है।

अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि ग्रामीण कौशल योजना ने 3.57 लाख नौकरियां और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने पिछले 4 वर्षो में 3.23 लाख नौकरियां उत्पन्न की है। साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) की गणना के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से अब तक 6.07 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने भी 1 लाख से अधिक सुरक्षा पदों और नई रेलवे परियोजनाओं के लिए भर्ती की है। पिछले 4.5 वर्षो में लगभग 2.22 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं, जिसने 6-8 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है। रिएलिटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने पहले 3 वर्षो में 1.2 करोड़ लोगो को रोजगार पैदा किया है और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022 तक 1.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेगा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं के अनुसार मोदी सरकार में रोजगार सृजन नहीं हुआ, किसी को नौकरी नहीं मिली, पर विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े बता रहे है कि 4 वर्षो में 15 करोड़ से अधिक नौकरियों/रोजगार/ स्वरोजगार का सृजन हुआ है। यह यह सारे तथ्य और आंकड़े जनता के सामने विपक्ष के नेताओं द्वारा बोले जा रहे झूठ की पोल खोलने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी की खाई को भरने की कोशिश की है बल्कि वायदों से भी बढ़कर कहीं ज्यादा काम किया है जबकि बेरोजगारी का रोना रोने वाली कांग्रेस पार्टी ही असल में बेरोजगारी की जननी है।

बायोमीट्रिक प्रणाली से खाद्यान्न वितरित न करने पर 31 हजार का जुर्माना

शिमला/शैल। जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक मिलाप शांडिल की अगुवाई में एक टीम ने नालागढ़ विकास खण्ड की विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की इस टीम द्वारा विभिन्न 12 डिपुधारकों से 31 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह जुर्माना राशि उचित मूल्य की दुकानधारकों द्वारा बायोमीट्रिक प्रणाली से खाद्यान वितरित न करने पर वसूला गया।

मिलाप शांडिल ने बताया कि फरवरी माह में नालागढ़ विकास खण्ड की 51 उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बायोमीट्रिक प्रणाली द्वारा खाद्य वस्तुओं की बिक्री नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गए थे। बावजूद इसके 12 उचित मूल्य की दुकानधारकों द्वारा अभी तक संतोषजनक कार्य नहीं किया गया था। इन डिपूधारकों द्वारा बायोमीट्रिक प्रणाली से खाद्यान्न वितरित करने पर उदासीनता दिखाई जिस कारण उनकी प्रतिभूति राशि जुर्माने के रूप में जब्त की गई है। जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक ने सभी डिूप धारकों से आग्रह किया है कि उपभोक्ताओं को बायोमीट्रिक प्रणाली के माध्यम से ही खाद्यान्न वितरित करें ताकि पात्र व्यक्तियों को ही खाद्यान्न वितरित हो तथा खाद्यान्नों का दुरूपयोग रूक सके। उन्होंने कहा कि जो भी उचित मूल्य की दुकानधारक बायोमीट्रिक प्रणाली से खाद्यान्न वितरण नहीं करेंगे उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा ऐसी स्थिति में उनकी उचित मूल्य की दुकान को रद्द भी किया जा सकता है।

मंडी में तैनात पोलिंग पार्टियों की रिहर्सल

मंडी/शैल। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए महाविद्यालय मंडी में सदर विधान सभा क्षेत्र-33 के लिए तैनात पोलिंग पार्टियों की प्रथम रिहर्सल करवाई गई। रिहर्सल में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े 854 अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रवण मांटा ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से निर्वाचन कार्य संपन्न करवाने के लिए अपने दायित्व को पूरी गंभीरता से निभाने को कहा। उन्होंने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन तय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम तथा वीवीपैट का मौके पर निरीक्षण करें, वीवीपैट पर उम्मीदवारों के नाम व पार्टी चिन्ह हैं या नहीं यह जांचना अति आवश्यक है। वीवीपैट की बैटरी को निकालकर सील करना भी सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि मतदान समय से 2 घण्टे पूर्व मतदान केन्द्र पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। पोलिंग ऐजेटों को मतदान शुरू होने से पहले बैठने का स्थान सुनिश्चित कर दें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदान का मौका दें।

इस मौके उपमण्डलाधिकारी सन्नी शर्मा ने चुनावी डियूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों से आहवान किया कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि पार्टी को मूव करने से पहले अपने पूरे सामान को भलीभांति जांच लें। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में किसी भी पार्टी के पोस्टर लगे हों तो उन्हें भी हटाना सुनिश्चित करें।

चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं के रेट तय

शिमला/शैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार ने पहले से जारी आदेश की निरंतरता में एक और आदेश जारी करते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आयोजित होने वाली जनसभाओं और कार्यक्रमों में उपयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं के रेट तय कर दिए है। रेट लिस्ट के मुताबिक ही चुनावी खर्च को जोड़ा जाएगा। रेट लिस्ट की सूचियां जिले के सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों के अलावा सहायक चुनाव पर्यवेक्षकों और व्यय निगरानी प्रकोष्ठ के इंचार्ज को भी सौंपी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसके अलावा विभिन्न आकार के मंचों, पुष्प मालाओं और कपड़े के बैनर के लिए पहले से अधिसूचित रेट में भी संशोधन किया है।

दिव्यांग मतदाताओं को उचित परिवहन सुविधा प्रदान करने हेतू नोडल अधिकारी नियुक्त

धर्मशाला/शैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव-2019 के दृष्टिगत दिव्यांग मतदाताओं को उचित परिवहन सुविधा प्रदान करने हेतु जिला स्तर की कमेटी का गठन किया गया है, जो वर्तमान लोक सभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन (19 मई, 2019) दिव्यांग मतदाताओं को उचित परिवहन सुविधा प्रदान करेगी।

उन्होंने बताया कि जिला स्तर की इस समिति में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला नोडल अधिकारी तथा जिला कल्याण अधिकारी, कांगड़ा व सचिव, रेडक्रास, कांगड़ा समिति के सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।

उन्होंने बताया कि समिति दिव्यांग मतदाताओं के साथ प्रत्येक लोकोमोटर व्यक्तियों की मतदान केन्द्रवार सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी और यह सुनिश्चित करेगी की उसके वोट देने के बाद उसे वापिस लेने और छोड़ने के लिए परिवहन सुविधा की अग्रिम व्यवस्था की गई है।

वाहनों की चेकिंग में वीडियोग्राफी करना जरूरी

सोलन/शैल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक नरेश कुमार बंसल ने उपायुक्त कार्यालय परिसर के कांफ्रेंस हॉल में सहायक निर्वाचन अधिकारियों और सहायक चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों के अलावा चुनावी व्यय की मॉनिटरिंग से जुड़े अधिकारियों की बैठक

ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यय पर्यवेक्षक ने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान वाहनों की चेकिंग के दौरान वीडियोग्राफी हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वाहनों की चेकिंग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष तौर से वाहनों की तलाशी के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि टीम इस प्रक्रिया के दौरान मर्यादित और सभ्य तरीके से पेश आए।

नरेश कुमार बंसल ने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महापर्व है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके के साथ संपन्न करवाई जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि स्टेटिक सर्विलांस टीमों और फ्लाइंग स्क्वायड टीमों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्टेटिक सर्विलांस टीमों की लोकेशन में बदलाव किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्टेटिक सर्विलांस टीम कौन से लोकेशन पर तैनात रहेगी यह संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों के निर्देश पर हो और इसकी पूरी जानकारी सहायक चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों को भी रहनी चाहिए कि टीम इस समय कौन सी जगह पर होगी।

व्यय पर्यवेक्षक ने ये भी निर्देश दिए कि सहायक निर्वाचन अधिकारी जब भी कोई अनुमति देते हैं तो उसकी प्रति तुरंत सहायक चुनाव व्यय पर्यवेक्षक को भी भेजी जाए ताकि उसी के अनुरूप शैडो रजिस्टर को मेंटेन करने का काम पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि किसी भी शिकायत पर कार्यवाही के दौरान निश्चित की गई प्रक्रिया के तहत ही कदम उठाए जाएं।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग और आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के दिशा निर्देशों के मद्देनजर चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मधुसूदन और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल के अलावा जिले के सहायक निर्वाचन अधिकारी, विभिन्न नोडल अधिकारी और सहायक चुनाव व्यय पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे।

''खोज एवं बचाव'' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

धर्मशाला/शैल। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा जिला के विभिन्न हिस्सों से आए स्वयंसेवी प्रतिभागियों के लिए आयोजित ''खोज एवं बचाव'' के आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। इस शिविर में नेहरू युवा केन्द्र तथा जिला युवा एवं खेल सेवाएं विभाग द्वारा जिला के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागी चुन कर भेजे गये। शिविर का आयोजन पर्वतारोही संस्थान धर्मशाला में किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने घायल को नदी या पहाड़ी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक रस्सी के माध्यम से ले जाने, घायल को बहुमंजिला ईमारत या पहाड़ी से निकालने/रस्सी से स्ट्रेचर बनाने जैसे गुर सीखे। इसके साथ ही प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार एवं आग से बचाव के तरीके भी सिखाए गये।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सभी प्रतिभागियों से अपनी-अपनी पंचायत में 10 स्वयं सेवी चिन्हित करने की अपील भी की गई जो पंचायत में आपदा प्रबंधन के लिए जागरूकता फैला सके।

इस अवसर पर जिला आपदा प्राधिकरण कांगड़ा के समन्वयक भानु शर्मा, रॉबिन कुमार उपस्थित थे।

कांग्रेस के आरोपों का जवाब लोकसभा चुनाव में देगी जनता:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि विगत पांच वर्षो में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की गिनती विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में होने लगी है तथा यह समय की मांग है कि यह गति न थमे इसके लिए फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। मुख्यमंत्री

मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शिवाबदार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने भारत के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इसके अंतर्गत देश के करोड़ों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। हालांकि इससे पूर्व केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन जनता की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने देश का विकास नहीं किया, उन्हें इस लोकसभा चुनाव में जनता अवश्य जवाब देगी।

जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश भाजपा सरकार ने मात्र एक साल के कार्यकाल के दौरान विधानसभा क्षेत्र द्रंग में 127 करोड़ रुपए के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए हैं। उन्हांने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान एक साल की अवधि में इस क्षेत्र में इतने कार्य नहीं किए गए, हालांकि द्रंग से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्ता में थे। उन्हांने कहा कि भाजपा सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा जमीन से जुड़े नेता हैं, वे जनता के सुख-दुख के साथी हैं ऐसे में इस बार उन्हें ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाना होगा। उन्हांने स्थानीय जनता से आग्रह किया कि द्रंग से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को बढ़त दिलाएं तथा प्रदेश भाजपा सरकार द्रंग के विकास को और गति देगी।

इस अवसर पर द्रंग में 36 परिवारों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा में शामिल होने वाले सभी सदस्यों का स्वागत-अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पं. सुखराम की सोच अपने परिवार तक ही सीमित है। उन्हें न तो प्रदेश के विकास से सरोकार है न ही उन्हें मण्डी के स्वाभिमान की चिन्ता है। उन्होंने कहा कि मण्डी जिले के लोग पं. सुखराम की इस हरकत से परेशान हो गए है और लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका उत्तर देगी। उन्होंने कहा कि लोग परिवारवाद की इस राजनीति से तंग आ चुके हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने सभी वर्गो का ध्यान रखते हुए सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जाति की राजनीति नही करनी परन्तु यह भाजपा के लिए गौरव की बात है कि भाजपा में अनुसूचित जाति के अधिक कार्यकर्ता है।

शिक्षण संस्थानों के माध्यम से वहेतों को खुश करने में लगी भाजपा

शिमला/शैल। जिला ऊना के राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौक के सहायक प्रोफेसर के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा की गई गुंडागर्दी तथा मारमीट की हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है तथा इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि यदि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच नही हुई तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुरे प्रदेश में सड़को पर उतरेगी।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा राज में देश व प्रदेश में अराजकता का माहौल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है तथा भाजपा से जुड़े लोगों की दादागिरी अधिकारी एवं कर्मचारी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा से जुड़े लोग मनमाफिक कार्य करवाने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। यदि कोई उनके तुगलकी फरमानों को मानने से इन्कार करता है तो वे सत्ता का रौब जमाते हैं जो कि इस शांत प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति के विरुद्ध है। कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि ऊना के राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौक के सहायक प्रोफेसर के साथ मारपीट की घटना हिमाचल प्रदेश के लिए शर्मनाक घटना है जिस राज में गुरु ही सुरक्षित नहीं है उस सरकार से आम नागरिक अपनी सुरक्षा की क्या उम्मीद कर सकता है।

उन्होने कहा कि भाजपा नेताओं की संस्कृति बन गई है कि सत्ता के नशे में चूर होकर वे लोकतंत्र की मर्यादाओं को भी भूल गये हैं। भाजपा नेता आये दिन सार्वजनिक मंचो से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनके राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक नेता राजनीतिक बौखलाहट में आकर लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करने पर तुले हुये हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए नैतिकता की सारी सीमाएं लांग रहे हैं। राठौर ने आरोप लगाते हुये कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक वर्ष के अधिक समय के भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से अराजकता का माहौल तैयार हुआ है वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है।

खोले जा सकते हैं पंडोह बांध के गेट, ब्यास किनारे न जाएं लोग

शिमला/शैल। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने कहा कि गर्मी के मौसम में ब्यास नदी के कैचमेंट एरिया में पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से पंडोह बांधा का जलस्तर निरन्तर बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण बांधा के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं। उन्होंने ब्यास नदी के आसपास के क्षेत्रें में रहने वाले लोगों व पर्यटकों से अपील की कि इस दौरान दरिया के किनारे न जाएं और पूरी एहतियात बरतें ताकि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके।

हमीरपुर में आयोजित होगा नेशनल डिवार्मिंग-डे

हमीरपुर/शैल। जिला में में पहली मई को नेशनल डिवार्मिंग डे का आयोजन किया जाएगा जिसमें जिला हमीरपुर के एक से 19 वर्ष तक की आयु वर्ग के 1 लाख 30 हजार 445 बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा एलवेंडाजोल टेबलेट खिलाई जाएगी। यह टेबलेट जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भी बच्चों को खिलाई जाएगी।

इस सम्बंध में अतिरिक्त उपायुक्त रत्न गौतम की अध्यक्षता में उनके चैंबर में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस दिन एक से 5 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों को एलवेंडाजोल के साथ 2 एमएल विटामिन-ए भी पिलाई जाएगी। एक से 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों को एलवेंडाजोल की आधी टेबलेट दी जाएगी जबकि 2 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को पूरी टेबलेट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में अध्यापक यह सुनिश्चित बनाएगे कि वह पहले स्वयं बच्चों के सामने टेबलेट को चबाएं तथा उसके बाद बच्चों को टेबलेट चबाकर खाने को कहें। उन्होंने कहा सभी सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को एलवेंडाजोल की टेबलेट मिड-डे-मील के बाद ही खिलाई जाए। किसी भी बच्चे को एलवेंडाजोल की टेबलेट खाली पेट न खिलाई जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जिला के समस्त स्कूलों तथा अन्य चिन्हित स्थानों पर समुचित मात्रा में समय पर एलवेंडाजोल टेबलेट तथा विटामिन-ए की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाएं।

उन्होंने कहा कि जो बच्चे पहली मई को छूट जाएंगे उन्हें मॉप अप डे के दौरान 8 मई को कवर किया जाएगा । उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में अध्यापक बच्चों को प्रात:कालीन सभा में एलवेंडाजोल तथा हैंड वाशिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दें, ताकि बच्चे विभिन्न प्रकार के रोगों से बचे रहें। इसके साथ स्कूल में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था को बनाए रखें।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को दिए जाएंगे अवॉर्ड

शिमला/शैल। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 19 मई को वोटर टर्नआउट को बढ़ाने की दिशा में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा किए गए प्रयासों को अवार्ड के माध्यम से पहचान दी जाएगी ताकि अन्य बीएलओ को भी प्रेरणा मिले।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि सोलन जिला के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के जिस मतदान केंद्र में सर्वाधिक मत प्रतिशतता रहेगी उस मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी को अवार्ड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन पांच अवार्ड के अलावा जिला स्तर पर भी एक अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड को सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में अव्वल रहे बूथ लेवल अधिकारियों में से उस अधिकारी को दिया जाएगा जिसकी मत प्रतिशतता सबसे अधिक रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के मकसद से स्वीप गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि वे 19 मई को अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अवश्य मतदान करें। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। सभी 557 बूथ लेवल अधिकारी हर संभव प्रयास करें कि उनके मतदान केंद्रों पर मतदान वाले दिन सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

ओल्ड एज हैल्पलाइन सोसायटी ने मनाया 17वां स्थापना दिवस

शिमला/शैल। ओल्ड एज हैल्पलाइन सोसायटी सोलन ने दुर्गा क्लब में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसायटी के वरिष्ठतम सदस्य प्रो. बीके सपरू ने की।

उन्होंने कहा कि सोसायटी के सदस्यों को चाहिए कि वे सोसायटी के साथ अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को जोड़ने का प्रयास करें ताकि युवा वर्ग भी सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान प्रदान कर सके।

सोसायटी के अध्यक्ष शैलेन्द्र कंवर ने कहा कि वर्ष 2003 में स्थापित यह सोसायटी निरंतर समाज के असहाय व जरूरतमंद लोगों की सहायतार्थ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सोसायटी के ये प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे।

उन्होंने सोसायटी के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे सोसायटी की हर गतिविधि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि सोसायटी के माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि भविष्य में सोसायटी द्वारा रैडक्रॉस तथा अन्नपूर्णा जैसी सामाजिक संस्थाओं से सांमजस्य बिठाकर समाज हित के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि सोसायटी ने गत वर्ष लगभग 76 हजार 435 रूपये एकत्रित हुए हैं इसमें से असहाय व जरूरतमंद व उपचाराधीन लोगों को 83 हजार 830 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि सोयायटी में अभी तक 128 सदस्य पंजीकृत है जिसमें 69 सदस्य सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सदस्य केडी बाली, आरके सतीजा को स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर सोसायटी के दो दिवंगत सदस्यों मदन स्परूप शर्मा एवं डीआर चौधरी की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम का संचालन आरके पठानिया ने किया। सोसायटी के महासचिव डॉ. बीएन कोरला ने सोसायटी की गत वर्ष की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की और अपने विचार रखें।

इस अवसर पर सुशील कुमार ने सोसायटी का वर्ष 2018-19 का लेखाजोखा भी प्रस्तुत किया तथा उत्कृष्ट कार्यकर्ता के सम्मान से नवाजा गया। सोसायटी द्वारा अगले दो वर्ष के भी कार्यकारिणी का चुनाव रिटर्निंग अधिकारी डॉ. केएल कुड़ एवं सहायक रिटर्निंग् अधिकारी रमेश कुमार की देखरेख में संपन्न हुए। जिसमें शैलेंद्र कंवर को अध्यक्ष, अजय शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसएस नाथ एवं कमलेश ऑबराय को उपाध्यक्ष, डॉ. बीएन कोरला को महासचिव, सुशील कुमार को वित्त सचिव चुना गया। इसी प्रकार प्रो. पठानिया को प्रेस सचिव चुना गया।

फर्जी फार्म भरने से रहें सावधान

शिमला/शैल। एसडीएम कांगड़ा जतिन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल कांगड़ा के अंतर्गत ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' योजना के नाम पर 8 वर्ष से 32 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के फर्जी फार्म भरवाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस योजना के तहत दो लाख रुपए मिलने और आवेदन-पत्र को भरकर भारत सरकार महिला व बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, दिल्ली-110001 के पत्ते पर भेजे जाने का हवाला दिया जा रहा है।

इस संबंध में आम जनता को सूचित किया है कि भारत सरकार ने ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' योजना में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत 8 से 32 वर्ष की आयु की लड़कियों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने बताया कि यह मात्र एक अफवाह है तथा इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की अफवाहें फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

क्या अब अभद्रता होगी चुनावी हथियार

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती द्वारा नालागढ़ के रामशहर में एक कार्यकर्ता सम्मलेन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए की चेयर पर्सन सोनिया गांधी के खिलाफ कहे गये अपशब्दों का कडा संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने सत्ती के चुनाव प्रचार पर 48 घण्टे के लिये रोक लगा दी है। लेकिन यह रोक लगने से पहले ही सत्ती के खिलाफ एक और शिकायत चुनाव आयोग के पास पहुंच गयी है। सत्ती ने नालागढ़ के रामशहर के बाद ऊना के अम्ब में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। सत्ती द्वारा की गयी अभद्रता पर मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर से लेकर उनके मन्त्रीयों तक ने कोई खेद व्यक्त करने की बजाये उनका परोक्ष/अपरोक्ष में यह कहकर समर्थन किया है कि यह अभद्रता कांग्रेस द्वारा प्रधानमन्त्री के खिलाफ प्रयोग की जा रही भाषा पर कार्यकर्ताओं की सहज प्रतिक्रिया का प्रतिफल है। भाजपा के प्रदेश चुनावी प्रभारी तीर्थ सिंह रावत ने भी इसी लहजे में सत्ती का बचाव किया है। सत्ती ने चुनाव आयोग को भेजे जवाब मे भी यही तर्क दिया है लेकिन आयोग ने इस तर्क को खारिज करते हुए अपना आदेश सुनाया है। इस तरह इस पूरे मामले से यह सामने आता है कि इस अभद्रता का प्रयोग एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है।

इस ''क्यों'' का जवाब खोजते हुए जो सामने आता है उसके मुताबिक आज जो सवाल राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक भाजपा और मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं उनका जवाब नही आ रहा है। क्योंकि आज मोदी सरकार सत्ता मे है तो सवाल तो उन्ही से पूछे जाने हैं क्योंकि 2014 के चुनावों मे जो वायदे भाजपा और मोदी ने देश/प्रदेश की जनता से किये थे वह पूरे तो हुए नही है। इन पर सवाल आते ही यह कह दिया जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया है इतने समय तक। यह तर्क है कि जब

कांग्रेस ने नहीं किया तो हम भी क्यों करे। हमारे से हिसाब क्यों पूछा जाये। हिसाब तो कांग्रेस से मांगा जा रहा है। इस तरह की वस्तुस्थिति में यह स्वभाविक है कि जब कोई तर्क पूर्ण जवाब नही रह जाता है तब सवाल की प्रतिक्रिया में अभद्रता का सहारा लिया जाता है। क्योंकि जब जनता को यह परोसा जाता है कि जो राहुल गांधी अभी तक बहू नही ला सके हैं वह देश को क्या संभालेंगे, कैसे प्रधानमन्त्री बनेंगे। यह एक ऐसा कमजोर तर्क है जिसका चुनाव जैसे गंभीर विषय के साथ कोई भी संबंध ही नही बनता है। लेकिन जनता जब ऐसे कथनों पर ताली बजाते हुए अपनी प्रतिक्रिया देती है तो नेता को लगता है कि जनता ने उसकी बात को समझ लिया है और उसका समर्थन कर रही है। लेकिन तब नेता यह भूल जाता है कि गाली को मिलाकर समर्थन वहीं तक रहता है यह स्थायी नही होता, क्योंकि गाली समझदारी की नही बल्कि अज्ञानता और हल्केपन की परिचायक होती है। आज शायद इसी हल्केपन को समर्थन मानने की भूल की जा रही है।

सत्ती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस नाते उनकी जिम्मेदारी एक तरह से मुख्यमन्त्री से भी बढ़ जाती है। क्योंकि उनसे यह पूछा जा सकता है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। सरकार के लिये कार्य एजैण्डा पार्टी तय करती है और उस ऐजैण्डा को अमली शक्ल मुख्यमन्त्री देता है। मुख्यमन्त्री से सरकार की कारगुजारी पर तो सवाल पूछा जा सकता है लेकिन पार्टी की कारगुजारी पर नहीं। आज जयराम सरकार भ्रष्टाचार के एजैण्डे पर पूरी तरह असफल है क्योंकि बतौर विपक्ष भाजपा ने भ्रष्टाचार के जो आरोप पत्र तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ सौंपे थे उन पर एक वर्ष में कारवाई के नाम पर कुछ भी सामने नही आया है। उल्टे आज जयराम के एक मंत्री का करीब पांच करोड़ का कांगड़ा के पालमपुर में किया गया निवेश चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी चुनावों की घोषणा के बाद सिमैन्ट के दाम बढ़ाये जाने पर जनता सवाल पूछ रही है। इस एक वर्ष के कार्यकाल में ही मन्त्री और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर सार्वजनिक रूप से पत्र छप जायें तो इन पर जनता पार्टी अध्यक्ष से लेकर मुख्यमन्त्री तक सबसे सवाल तो पूछेगी ही। सत्ती के जिले में ही किसानों को दिये गये दो-दो हजार रूपये उनके खातों से बैंकों ने बिना कारण बताये सरकार को वापिस कर दिये। लेकिन सरकार और संगठन में से किसी ने भी इस पर जवाब नही दिया है। जिन किसानों के साथ यह घटा है क्या वह आज सवाल नही पूछेंगे। आज स्कूलों में अध्यापकों और अस्पतालों में डाक्टरों की भारी कमी चल रही है। अभी चुनाव ड्यूटी के कारण कई स्कूलों में तो कोई अध्यापक ही नही रहा है। प्रशासन की सबसे बड़ी लाचारता और क्या हो सकती है। प्राईवेट स्कूलों की लूट को लेकर छात्र अभिभावक मंच कई दिनों से आन्दोलन पर है। सरकार उच्च न्यायालय और अपने ही आदेशों की अनुपालना नही करवा पा रही है। जिससे स्पष्ट झलकता है कि इस लूट को सरकार का समर्थन हासिल है। इस तरह दर्जनों ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका सरकार और संगठन के पास कोई सन्तोषजनक उत्तर नही है और भाजपा इन सवालों से कांग्रेस और राहुल गांधी को गाली देकर बचने का प्रयास कर रही है।

इस परिदृश्य में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि जब सरकार मंहगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे अहम क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से पूरी तरह असफल हो गयी है तो वह चुनावी मोर्चे पर महज गाली देकर सफल हो पायेगी। इसी के साथ कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि प्रदेश भाजपा के अन्दर आज जो खेमेबाजी की झलक चल रही है सत्ती का इस तरह गाली देना कहीं न कहीं उस खेमेबाजी की झलक भी देता है। क्योंकि सत्ती ने राहुल, सोनिया और प्रियंका के साथ-साथ राधा स्वामी संतसंग ब्यास को लेकर भी प्रतिकूल टिप्पणी की है। इस टिप्पणी से पूरा राधा स्वामी समाज नाराज हुआ है। जबकि कांगड़ा और हमीरपुर के संसदीय क्षेत्रों में राधा स्वामी समाज का बहुत प्रभाव है इस समाज की नाराज़गी इन सीटों पर भारी पड़ सकती है। राहुल गांधी परिवार के खिलाफ की गयी टिप्पणी को यदि राजनीतिक कारणों से जोड़ते हुए नजर अन्दाज कर भी दिया जाये तो उसी तर्क से राधा स्वामी समाज के खिलाफ आयी टिप्पणी को लेकर ऐसा नही किया जा सकता। हालांकि सत्ती ने इस पर खेद भी जता दिया है लेकिन इस खेद से यह और स्पष्ट हो जाता है कि इस टिप्पणी का एक अलग ही मंतव्य था।

क्या प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को पर्यावरण नियमों /कानूनो की ही जानकारी नही है एनजीटी के आदेश से उठी चर्चा

शिमला/शैल। प्रदूषण नियन्त्रण और पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिये ही केन्द्र से लेकर राज्यों तक प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डो का गठन किया गया है। क्योंकि आज अर्न्तराष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी चिन्ता पर्यावरण है। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलनों और मंचो पर यह चिन्ता वयक्त की जा चुकी है। यूएन इस संद्धर्भ में कड़े नियम बना चुका है और सदस्य देश इन नियमों की पालना को बाध्य हैं। प्रदूषण और पर्यावरण की इसी गंभीरता का संज्ञान लेते हुए वीरभद्र शासनकाल के दौरान एनजीटी ने प्रदेश के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और इसके अध्यक्ष की शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर सवाल उठाया था और यह आदेश जारी किये थे कि इन पदों पर उन्हीं लोगों को तैनात किया जाये जिनके पास इस विषय की अनुकूल योग्यताएं हो।

प्रदेश में जब होटलों एवम् अन्य अवैध निर्माणों को लेकर उच्च न्यायालय में याचिकाएं आयी थी तब अदालत ने पर्यटन टीसीपी, लोक निर्माण के साथ-साथ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से भी जवाब तलबी की थी। इसी जवाब तलबी की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कसौली कांड घटा था। एनजीटी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और टीसीपी के कुछ लोगों के खिलाफ नाम लेते हुए कारवाई करने के आदेश दिये थे। अदालत की इस सारी गंभीरता से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदूषण और पर्यावरण की गंभीरता क्या है। लेकिन क्या अदालत की इस गंभीरता का सरकार और प्रदूषण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर कोई असर पड़ा है। इसका जवाब अभी 26-3-2019 को एनजीटी से आये एक आदेश के माध्यम से सामने आ जाता है।

एनजीटी के साप कांगड़ा के मण्डक्षेत्र में हो रहे अवैध खनन का एक मामला मंड पर्यावरण संरक्षण परिषद के माध्यम से आया था। यह मामला आने के बाद कलैक्टर कांगड़ा और प्रदेश के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से 21-12-2018 को जवाब मांगा गया था। इस पर बोर्ड ने 6-3-2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। शपथपत्र के साथ दायर हुई इस रिपोर्ट में बोर्ड ने सीधे कहा कि यह अवैध खनिज खनन का मामला उनके अधिकार क्षेत्र में ही नही आता है। यह उद्योग विभाग के जियोलोजिकल प्रभाग का मामला है जो कि 1957 के खनिज अधिनियम के तहत संचालित और नियन्त्रित होता है।

प्रदूषण बोर्ड के इस जवाब का कड़ा संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने यह कहा है कि शायद बोर्ड सदस्य सचिव को पर्यावरण के नियमों का पूरा ज्ञान ही नही है। पर्यावरण को लेकर प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एनजीटी ने अपने आदेश में प्रदेश के मुख्य सचिव को भी निर्देश दिये हैं कि वह बोर्ड के सदस्य सचिव को पर्यावरण नियमों का पूरा ज्ञान अर्जित करने की व्यवस्था करें। एनजीटी का यह आदेश राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है क्योंकि इस आदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि या तो सदस्य सचिव को सही में ही पर्यावरण नियमों का ज्ञान नही है और उनकी नियुक्ति एनजीटी के पूर्व निर्देशों के एकदम विपरीत की गयी है। यदि यह नियुक्ति एनजीटी के मानकों के अनुसार सही है तो फिर निश्चित रूप से बोर्ड अवैध के दोषीयों को किसी के दबाव में बचाने का प्रयास कर रहा है सबसे रोचक तो यह है कि एनजीटी का यह आर्डर 26 मार्च को आ गया था। लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नही किया गया है। क्योंकि या तो सदस्य सचिव को पर्यावरण नियमों की जानकारी/योग्यता हासिल करने के निर्देश दिये जाते या फिर उनकी जगह किसी दूसरे अधिकारी को तैनात किया जाता जो एनजीटी के पूर्व के निर्देशों अनुसार शैक्षणिक योग्यता रखता हो। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नही है और इसी से सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठता है।

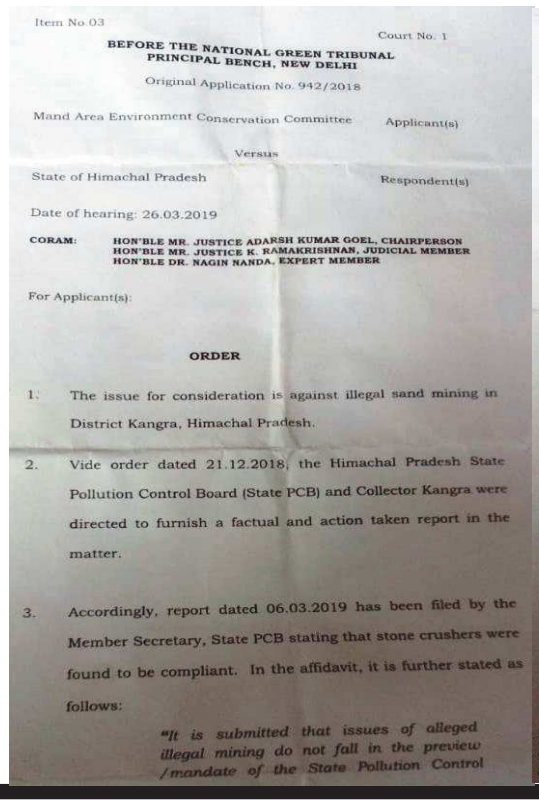

Item No.03 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 942/2018

Mand Area Environment Conservation Committee Applicant(s)

Versus

State of Himachal Pradesh Respondent(s)

Date of hearing: 26.03.2019

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s):

ORDER

1. The issue for consideration is against illegal sand mining in District Kangra, Himachal Pradesh.

2. Vide order dated 21.12.2018, the Himachal Pradesh State Pollution Control Board (State PCB) and Collector Kangra were directed to furnish a factual and action taken report in the matter.

3. Accordingly, report dated 06.03.2019 has been filed by the Member Secretary, State PCB stating that stone crushers were found to be compliant. In the affidavit, it is further stated as follows:

"It is submitted that issues of alleged illegal mining do not fall in the preview /mandate of the State Pollution Control Board and illegal mining is to be checked by the Geological wing of Industries Department under Mines & Mineral Act, 1957."

4. We find that the above statement shows lack of knowledge of environmental law on the part of the Member Secretary, State PCB. The environment norms can certainly be overseen by the State PCB even if there is some overlapping. Mining Department may mainly oversee the compliance of Mining laws. The State PCB cannot disown the responsibility of overseeing the monitoring and compliance of environmental norms.

5. In view of the above, we dispose of this matter with a direction to the Chief Secretary, Himachal Pradesh to appropriately counsel the Member Secretary, State PCB so that he can acquire minimum knowledge required for performing his duties. A copy of this order be sent to the Chief Secretary, Himachal Pradesh for the purpose by e-mail.

Adarsh Kumar Goel, CP

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

March 26, 2019
Original Application No. 942/2018
A